मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर में नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी और खोरा बीसल में तीन नए पुलिस थानों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीएलजी सदस्य उपस्थित थे।

नये थानों से अपराध नियंत्रण व महिला सुरक्षा को गति मिलेगी -भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जयपुर में नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी व खोरा बीसल में नये थानों का शुभारंभ किया

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस का रैस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए 25 इन्टरसैप्टर वाहन, 250 मोटर साइकिलें और 500 मोबाइल यूनिट वाहन प्रदान किये गये हैं।**

जयपुर, 29 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर में नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी और खोरा बीसल में तीन नए पुलिस थानों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सरकार के कार्यकाल में अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पुलिसिंग के लिए 22 नए पुलिस थानों का सृजन, 8 चौकियों का थानों में क्रमोन्नयन तथा 35 नई पुलिस चौकियों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, जयपुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए एक नया थाना और 9 चौकियों की स्थापना हेतु 255 पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है। इसके साथ ही, पद्मिनी, काली बाई और अमृता देवी नामक तीन नई महिला बटालियन गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तैनात की गई हैं और महिला हेल्पलाइन 1090 के माध्यम से त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, गिरफ्तार व्यक्तियों और गुमशुदा लोगों की जानकारी अब पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिलें और 500 मोबाइल यूनिट वाहन प्रदान किए गए हैं। साथ ही, एफएसएल में 123 नए पद सृजित कर जांच की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नारायण विहार थाना परिसर का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा अन्य थानों का वर्चुअली लोकार्पण किया। कार्यक्रम में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीएलजी सदस्य और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

'राहुल को धमकी देने वाले पर कार्यवाही क्यों नहीं?

■ **कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि यह धमकी आवेश में की गई टिप्पणी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।**

नयी दिल्ली, 29 सितम्बर। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह हैरानी की बात है कि भाजपा गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले अपने प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।

पार्टी ने सोमवार को कहा कि भाजपा प्रवक्ता की यह धमकी अतिश्योक्ति नहीं है, बल्कि सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। गांधी को पहले भी विभिन्न अवसरों पर धमकियां दी जाती रही हैं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता की लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी को लाइव टेलीविजन शो पर जान से मारने की यह धमकी उसकी मंशा पर गंभीर सवाल उठाती है।

कांग्रेस ने एक बयान में सवाल किया कि क्या गांधी के खिलाफ कोई बड़ी और भयावह साजिश हो रही है, इसलिए भाजपा जान से मारने की धमकियों की राजनीति का समर्थन करती है। अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा को तत्काल अपने प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

कांगेस का कहना है कि यह अत्यंत गंभीर मामला है, इसलिए पार्टी नेता के सी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कैनडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया

कैनडा सरकार ने दावा किया कि बिश्नोई गैंग देश में कई गैंग वॉर व हत्याओं में शामिल है

■ **कैनडा के कई राजनेताओं ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर प्रतिबंध की माँग की थी। जून में ब्रिटिश कोलम्बिया में प्रधानमंत्री ने तथा जुलाई में अल्बर्टा के प्रधानमंत्री ने इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।**

ओटावा, 29 सितंबर। कैनडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कैनडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंगवार और हत्याओं में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। कैनडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने घोषणा की कि कैनडा ने बिश्नोई गिरोह को देश की आपराधिक संहिता के तहत, आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, आनंदसांगरी ने लिखा, "आज हमारी सरकार ने बिश्नोई गिरोह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। कैनडा में हिंसा, आतंक और समुदायों को धमकाना कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

कैनडा के कई राजनेताओं ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर प्रतिबंध की मांग की थी। 17 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री डेविड एबी ने कहा, "आतंकवादी घोषित किए जाने से पुलिस को इस गतिविधि की जांच करने और उसे रोकने के लिए आवश्यक उपकरणों का उपयोग करने में मदद मिलती है। इससे पुलिस को महत्वपूर्ण जांच टूल्स मिलते हैं।" जुलाई में, अल्बर्टा के प्रधानमंत्री डैनियल स्मिथ ने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर प्रतिबंध की मांग की थी।(कैनडा की अपराध निरोधक राज्य सचिव रूबी सहोता ने कहा कि अगर कोई समूह आतंकवादी समूह होने के पैरामीटर्स पर आधारित है तो उसे बिना कोई देरी किए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।

14 मई को कैनडा के टोरंटो में 51 वर्ष के हरजीत सिंह ढ ड्डा की उनके ऑफिस के पॉर्किंग में हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने हरजीत को गोलियों से छलनी कर दिया था। उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बाद में बिश्नोई गैंग से जुड़े दो लोगों ने फेसबुक पोस्ट में हरजीत की हत्या की जिम्मेदारी ली थी।

घाटी में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कश्मीर संभाग में जिन सात टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोला गया, उनमें अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क और कमान पोस्ट शामिल हैं।

इसके अलावा, जम्मू संभाग में भी 5 पर्यटन स्थलों को खोला गया है, जिनमें डगन टॉप (रामबन), धग्गर (कठुआ), शिव गुफा (सालाल, रियासी) शामिल हैं। इससे पहले, जून महीने में प्रशासन ने 16 अन्य पर्यटन स्थलों को भी फिर से खोला था, जिनमें पहलगाम के कुछ हिस्से भी शामिल थे।

पाक अधिकृत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने पाकिस्तानी प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर संचार व्यवस्था ठप कर रहा है, ताकि क्षेत्र को अलग-थलग किया जा सके और सूचना प्रवाह रोका जा सके।

पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक शक्तियों से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करें और 13 मई 2024 जैसी एक और त्रासदी को रोकें, जब मुज़फ्फराबाद में पाकिस्तानी रेंजरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई थी, जिसमें तीन नागरिकों की मौत हुई थी, यह मामला अब भी अनसुलझा है।

पार्टी का कहना है कि पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान अभी भी राजनीतिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र हैं, जहां नागरिकों को बोलने, चलने और स्व-शासन के अधिकार नहीं दिए जाते। यह एक ऐसा आरोप है, जो पाकिस्तान के कश्मीरी आत्मनिर्णय के झूठ को उजागर करता है। यह संकट चीन के रणनीतिक समीकरण को भी जटिल बना सकता है, क्योंकि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कुछ हिस्से गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरते हैं। यदि अस्थिरता बढ़ी, तो इससे निवेश प्रभावित होगा, पाकिस्तान की कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ेगा तथा बीजिंग-इस्लामाबाद संबंधों में खटास आ सकती है।

यह संकट महज़ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है - यह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले क्षेत्रों में विफल शासन का जनमत संग्रह है। दुनिया देख रही है, और इस्लामाबाद के पास अब सिर्फ दो विकल्प हैं सुधार और संवाद के रास्ते से आगे बढ़ना, या पाक अधिकृत कश्मीर को एक और सुरक्षा संकट में बदल देना।

भारत और वैश्विक समुदाय के लिए संदेश स्पष्ट है कि पाक अधिकृत कश्मीर के सुखी होने का भ्रम टूट चुका है।" अब जो सामने आ रहा है, वह एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने बुनियादी अधिकारों की माँग कर रहा है, और ऐसा करते हुए, वह दक्षिण एशिया के राजनीतिक भूगोल को नए सिरे से गढ़ रहा है।

क्रिकेट मैच के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने रुख के चलते, 1974 में रोडेशिया के खिलाफ डेविस कप टेनिस फाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया था। वर्ष1971 में, जब भारत-पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था, तब भी दोनों देशों के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेष विश्व 'रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड' टीम का हिस्सा थे। कहा जाता है कि उस समय भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक ही कमरे में ठहरे थे।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मैदान पर हुआ यह ड्रामा दुर्भाग्यपूर्ण था और मौजूदा रिश्तों को देखते हुए, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला नहीं करना चाहिए था।

भारतीय रेल नैटवर्क से जुड़ेगा भूटान

भारत सरकार ने 4 हज़ार करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी दी

■ **रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी और कहा, यह रेलें बिजली से चलेंगी, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा।**

नयी दिल्ली, 29 सितम्बर। भारत ने रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भूटान को अपने रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए सोमवार को कुल चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की दो महत्वाकांक्षी रेल-मार्ग परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की।

इसका निर्माण पूरा होने पर भूटान के दो शहर गेलेफू और समत्से क्रमश: असम और पश्चिम बंगाल से सीधे रेलगार्म से जुड़ जायेंगे। इससे दोनों देशों के बीच यात्री और माल परिवहन में भारी सुधार होगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इनमें से पहली परियोजना असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू और दूसरी पश्चिम बंगाल के बनारहाट से समत्से के बीच रेल संपर्क के लिए तैयार की गयी है । उन्होंने बताया कि बनारहाट और भूटान के औद्योगिक शहर समत्से के बीच 16 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन विकसित की जायेगी और यह लाइन भूटान को पहली बार रेल संपर्क से जोड़ेगी।

भूटान के महत्वपूर्ण शहर गेलेफू को कोकराझार से जोड़ने वाला रेल मार्ग करीब 70 किलोमीटर लंबा होगा। इस तरह इन परिजनाओं से भूटान में पहली बार करीब 90 किलोमीटर के रेल मार्ग उपलब्ध होंगे, जो भारतीय रेल-नेटवर्क से जुड़े होंगे।

रेल मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं को चार साल में पूरा किया जाएगा और इन पर करीब 4033 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। भूटान के लिए विकसित किये जाने वाली रेलवे लाइनों को वंदेभारत रेल चलाने के अनुकूल बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भूटान के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसका बाहरी दुनिया के साथ अधिकांश व्यापार भारतीय बंदरगाहों और भारत के सड़क मार्गों के माध्यम से होता है। प्रस्तावित रेलवे नेटवर्क के तैयार होने के बाद भूटान की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा।

भूटान को जोड़ने वाली रेल लाइनें बिजली से संचालित होंगी है और इस तरह रेल परिचालन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा।

'गौतम-शिल्पी मर्डर केस में लिप्त थे सम्राट चौधरी'

पटना, 29 सितंबर। "जन सुराज" प्रमुख प्रशांत किशोर ने गौतम-शिल्पी मर्डर केस में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की संलिप्ता का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का नाम लेकर कहा कि बेहतर होगा कि वे खुद इस मामले में अपनी संलिप्ता को लेकर जवाब दे दें। वे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग अपने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले से जुड़े साक्ष्य को जारी कर पूरी कहानी बता देंगे। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई ने बिहार के सबसे चर्चित शिल्पी हत्याकांड में साधु यादव के अलावा, सम्राट चौधरी को भी अभियुक्त बनाया था। सीबीआई की टीम ने सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार से लंबी पूछताछ भी की थी। उनका सैंपल भी लिया गया था। लेकिन तत्कालीन लालू- राबड़ी सरकार ने साधु यादव को बचाने के लिए पूरे मामले को रफा दफा कर दिया था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, 1997-1998 में ही मुझे कोर्ट ने बरी किया है। उनके आरोपों में दम नहीं है।

सहयोग पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा एक्स

एक्स ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, ताकि "फ्री स्पीच" की रक्षा हो सके

■ **सहयोग पोर्टल के जरिए देश भर के पुलिस अधिकारियों को अधिकार मिल गया है कि वे कोई भी "कन्टैंट" सोशल मीडिया से हटा सकते हैं।**

नई दिल्ली, 29 सितंबर। एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर विवादों के केन्द्र में आ गया है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिसमें सरकार के "सहयोग पोर्टल" को मंजूरी दी गई है। इस पोर्टल के जरिए, देशभर के करीब 20 लाख पुलिस अधिकारियों को कंटेंट हटाने का अधिकार मिल गया है।

एक्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "हम इस आदेश को चुनौती देंगे, ताकि फ्री स्पीच की रक्षा की जा सके।" कंपनी का आरोप है कि सहयोग पोर्टल अधिकारियों को सिर्फ अवैधता के आरोप के आधार पर कंटेंट हटाने का आदेश देने का अधिकार देता है। इसमें न तो न्यायिक समीक्षा होती है और न ही प्रभावित यूज़र्स को कोई सुनवाई का मौका मिलता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर गैर-अनुपालन करने पर आपराधिक कार्रवाई का खतरा भी रहता है। एक्स और भारत सरकार के बीच कंटेंट हटाने को लेकर यह पहली लड़ाई नहीं है। पहले भी कंपनी कई बार सरकार के आदेशों को सेंसरशिप करार दे चुकी है। एलन मस्क खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट बताते हैं और कई देशों की सरकारों के साथ कंटेंट मॉडरेशन को लेकर उनका टकराव रहा है।

यह पोर्टल अक्तूबर 2023 में शुरू किया गया था। इसके जरिए अधिकृत अधिकारी सीधे टैक कंपनियों तक कंटेंट हटाने का आदेश भेज सकते हैं। हाईकोर्ट ने हाल ही में इसे वैध करार दिया था, जिसके खिलाफ अब एक्स अपील करेगा।अब अदालतों में होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।

महाराष्ट्र में भारी बारिश, दो दिन में 10 की मौत

मुंबई, 29 सितंबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और मुंबई उपनगरीय, रायगढ़ , ठाणे और पालघर सहित, चार अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

यह चेतावनी तटीय महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बीच जारी की गई है, मुंबई में इस मानसून सीजन में 3,000 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा पार हो गया है।

अधिकारियों के अनुसार, 48 घंटों से अधिक समय में पूरे महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम दस लोगों की जान चली गई, जबकि देर रात तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 11,800 से अधिक लोगों को बचाया गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि अकेले नासिक जिले में चार मौतें हुईं, धाराशिव और अहिल्यानगर में दो-दो मौतें हुईं, और जालना और यवतमाल जिलों में एक-एक मौत हुई।

चीन खुले दिल और मुक्त हाथों से डॉक्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिक्षित वैज्ञानिक पहले से ही चीन लौट रहे थे और यह एक मजबूत और शायद "अपरिवर्तनीय" प्रवृत्ति थी।

स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार विकसित करने की पहल कोई और नहीं बल्कि स्वयं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा निरंतर की जा रही है। वे लंबे समय से चीनी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करते आ रहे हैं। हाल ही में एक सैन्य प्रदर्शनी में चीन ने जिस अत्याधुनिक तकनीक और हाई-टेक रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन किया, वह तो बस शुरुआत भर है।

असल में, चीन के पास ऐसे नतीजे पाने के दो बड़े कारण हैं। पहला, देश में उच्चतम स्तर पर स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता। कहा जाता है कि "किसी राष्ट्र की तरक्की उसकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति से होती है।"

ऐसे समय में, जबकि अमेरिका विदेशी प्रतिभाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सख्त वीज़ा नियम लागू कर रहा है, तब चीन प्रमुख और युवा वैज्ञानिकों व तकनीकी विशेषज्ञों के लिए "के" वीज़ा नाम का नया वीज़ा प्रोग्राम ला रहा है।

दूसरा, चीन के पास इतना बड़ा कोष है कि वह विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे क्षेत्रों में भी निवेश कर सकता है जिनका तुरंत कोई उपयोग न हो, लेकिन भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है। चीनी संस्थान और शोध निकाय आर्टिफिशल इन्टैलिजैंस, रोबोटिक्स और नेटवर्क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें लगभग पाँच लाख डॉलर तक के पैकेज दे रहे हैं। शीर्ष स्तर से मिले इन साफ निर्देशों के साथ चीन, ट्रम्प प्रशासन की सख्ती और एन्टी-इमिग्रेशन माहौल में फंसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षक पद और सुविधाएं देकर लुभाने की कोशिश कर रहा है। एच-1बी वीज़ा पर ऊंची फीस लगाने की डॉनल्ड ट्रम्प की "अदूरदर्शी" नीति ने उच्च प्रतिभाओं, मुख्य रूप से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों, में डर पैदा कर दिया है, जिन्हें अब प्रतिद्वंदी देश अपने यहां बुलाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे हालात में ट्रम्प प्रशासन की कार्रवाइयों पर सिर्फ शिकायत करने के बजाय भारत को युद्धस्तर पर पूरी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं और धन उपलब्ध कराना चाहिए, अगर वे अमेरिका से बाहर आने का सोचते हैं। क्योंकि इस शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने की होड़ बेहद प्रतिस्पर्धी और महंगी भी हो सकती है। पहले से ही अमेरिका का उत्तरी पड़ोसी देश कैनडा सक्रिय हो चुका है। कैनडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस सप्ताह वॉशिंगटन में काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स के सामने कहा कि अमेरिका के वीज़ा नियमों में बदलाव पर उनकी नज़र है। उन्होंने कहा, "शायद हम उनमें से कुछ को अपने यहां ला सकें।"

कार्नी, वीज़ा परिवर्तनों से प्रभावित लोगों के लिए कैनडा को एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, जहाँ वे अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नया कर व जगह पा सकते हैं। देश में अनेक विश्वस्तरीय संस्थान और शोध संगठन हैं जो ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

जर्मनी भी ऐसा ही कर रहा है और उसे उम्मीद है कि अमेरिका से निकले शीर्ष प्रतिभाशाली लोग उसके देश को विकल्प के रूप में देखेंगे। भारत में जर्मन राजदूत विशेष रूप से इस बात की सराहना करते हैं कि भारतीयों ने सिलिकॉन वैली की कंपनियों और व्यापक रूप से शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य जगहों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है।

जो देश अब शीर्ष प्रतिभाओं को पाने की होड़ में हैं, उनमें सबसे बड़ा आकर्षण बनकर जो देश उभर रहा है वो है चीन। इसकी वजह यह है कि चीन के पास पैसा है और पूरे देश में संस्थानों का ऐसा जाल है जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और एसटीईएम (स्टैम) क्षेत्र के लोगों को जगह दे सकता है।

चीन मुख्य रूप से प्रवासी चीनी नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन वह अन्य देशों के विशेषज्ञों का भी उतना ही स्वागत करता है। चीन, खासतौर पर रक्षा और सैन्य एप्लिकेशन्स में, अपने तकनीकी आधार को विकसित करने में अत्यधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है।

तथापि, अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक खिलाड़ी, एक प्रमुख अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर नवाचार और विकास के केन्द्र के रूप में बना रहना चाहता है, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन ने समझ लिया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी भी देश की प्रगति की असली ताकत है और उसने शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और इसके लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने की योजनाएं बना ली हैं।

सौभाग्य से भारत के पास उच्च विज्ञान संस्थानों की अच्छी श्रृंखला है। भारत के पास इस समय उच्च विज्ञान और इंजीनियरिंग के शोध प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा भी है। इन्हें तकनीक और क्षमता के तेज विकास को बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सच है कि पहले से मौजूद एक मजबूत ढांचे के साथ विदेश से आने वालों को समायोजित करना कठिन हो सकता है, लेकिन नए पदों पर इन्हें लाकर व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है।

किसी भी हाल में, ट्रम्प की इस कठोर नीति से बाहर हुए प्रतिभाशाली लोगों को समाहित करने के लिए भारत को अब संरचनाएं विकसित करने की शुरुआत करनी ही चाहिए। कम से कम नए और युवा प्रतिभाशाली लोगों को तो यहीं रोकने की कोशिश की जा सकती है, ताकि वे सपनों की किसी दूसरी धरती की ओर भागने के बजाय अपने ही देश में बने रहें।

मोदी ने दिल्ली भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 29 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नये कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही, दिल्ली भाजपा को राजधानी के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थायी कार्यालय मिल गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर दिल्ली के 14 जिलों के भाजपा कार्यालयों का भी रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। मोदी ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा कार्यालय किसी मंदिर और देवालय से कम नहीं हैं।

उन्होंने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से आव्हान किया कि भाजपा कार्यालय जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का केन्द्र बनें, इसके लिए आप सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो।

मोदी ने कहा कि दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय की पहचान यहां की सुविधाओं से नहीं बल्कि जनसुनवाई और जन सेवा से होनी चाहिए, यह बात हम सभी को हमेशा याद रखनी होगी।

अडानी को प्रॉपर्टीज़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आवेदन में कहा गया, "24,030 करोड़ की कुल मूल राशि में से, सहारा समूह ने लगभग 16,000 करोड़ की राशि वसूल की है और इसे उपरोक्त खाते में जमा किया है।"

सेबी द्वारा सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने में असफलता की ओर इशारा करते हुए, एसआईसीसीएल ने कहा कि रिफंड खाते में जमा की गई पूरी राशि केवल सहारा समूह के प्रयासों से ही एकत्र की गई। एसआईसीसीएल ने आगे बताया कि नवंबर 2023 में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद, समूह ने अपना एकमात्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति खो दिया। परिवार के सदस्य अब दैनिक व्यावसायिक संचालन में शामिल नहीं हैं और वे निवेशकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया कि यह निर्णय सभी हितधारकों के हित में लिया गया है, ताकि उनके दावे उचित रूप से संतुष्ट किए जा सकें और उन्हें अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। हालांकि, बाजार की मौजूदा स्थिति और उपयुक्त खरीदारों की अनुपस्थिति के कारण प्रयासों को सफलता नहीं मिल पायी है। इन प्रयासों को उस समय और भी जटिल बना दिया गया, जब कई जांच एजेंसियों ने सुब्रत रॉय के परिवार के सदस्यों और समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। 6 सितंबर की टर्म शीट के तहत 88 संपत्तियों की बिक्री को लेकर अदालत से अनुमति मांगते हुए समूह ने कहा कि प्रस्तावित सौदा एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जिससे समूह द्वारा अदालत के आदेशों के तहत निभाई जाने वाली वित्तीय जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

प्र.मंत्री मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

योगदान दिया है। रूपा पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित इस आत्मकथा का विमोचन सात अक्टूबर को किया जायेगा। इटली की प्रधानमंत्री ने इस आत्मकथा में अपनी कहानी अपने शब्दों में साझा करते हुए बताया है कि कैसे उन्होंने गारबेटेला में मजदूरों की बस्ती में अपना बचपन गुजारने से लेकर इटली की प्रधानमंत्री बनने तक का कठिन सफर तय किया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600